दैनिक जागरण

सपने और लक्ष्य में सिर्फ योजना का फर्क होता है

एकजुटता का प्रदर्शन

पुलवामा में भीषण आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सभी राजनीतिक दलों की ओर से जो एकजुटता दिखाई गई वह समय की मांग थी। यह अच्छा हुआ कि इस सर्वदलीय बैठक में आतंकवाद को नष्ट करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के साथ ही सीमा पार आतंकवाद की कड़े स्वर में निंदा भी की गई, लेकिन यह समझ नहीं आया कि पाकिस्तान का नाम लेने से क्यों बचा गया? आखिर जब पुलवामा हमले के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से आधिकारिक रूप से यह कहा गया कि पाकिस्तान इस हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद पर लगाम लगाए तब फिर सर्वदलीय बैठक में पाकिस्तान का जिक्र क्यों नहीं हो सका? यह ठीक नहीं कि पुलवामा हमले के बाद जब अमेरिका तक साफ तौर पर कह रहा है कि पाकिस्तान अपने यहां के आतंकी संगठनों को सुरक्षित ठिकाना उपलब्ध कराने से बाज आए तब भारत के राजनीतिक दल ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं कर सके जिसमें पाकिस्तान का साफ-साफ नाम लिया गया होता। यह एक तर्क हो सकता है कि पाकिस्तान का नाम लेने या न लेने से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दुनिया जान रही है कि भारत का यही पड़ोसी देश है जो किस्म-किस्म के आतंकी संगठनों को पालने-पोसने का काम कर रहा है। बावजूद इसके यह सवाल तो उठता ही है कि आखिर सर्वदलीय बैठक में पारित प्रस्ताव की भाषा यह क्यों नहीं कहती कि भारत को अपने जिस पड़ोसी देश की शत्रुतापूर्ण हरकतों से निपटने की जरूरत है वह पाकिस्तान है? हमारे राजनीतिक नेतृत्व को यह समझने की जरूरत है कि पुराने तौर-तरीकों से काम चलने वाला नहीं है। तौर-तरीकों के साथ हमारी भाषा भी बदलनी चाहिए, क्योंकि इससे ही मानसिकता बदलती है। क्या यह बेहतर नहीं होता कि सर्वदलीय बैठक में पारित प्रस्ताव में देश की संकल्पशक्ति की स्पष्ट झलक मिलती?

सर्वदलीय बैठक में जहां सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि वह वह पुलवामा हमले का मुंहतोड़ जवाब देगी वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी यह कहा कि वे सरकार के साथ हैं। यह महज औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। इस समय राजनीतिक नेतृत्व को देश के साथ दुनिया को यह दिखाने और साफ-साफ बताने की जरूरत है कि संकट के समय वह पूरी तौर पर एकजुट है। दुनिया को यह भी संदेश जाना चाहिए कि इस बार भारत तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक आतंकवाद को खाद-पानी दे रही ताकतों को सबक नहीं सिखाता। ऐसे प्रस्ताव जमीन पर भी उतरने चाहिए। ध्यान रहे कि एक समय संसद ने यह प्रस्ताव पारित किया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय भू-भाग को वापस लिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या कभी इस प्रस्ताव के अनुरूप कदम उठाए गए? यह अच्छा हुआ कि सर्वदलीय बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सांप्रदायिक सदभाव बनाए रखने की जरूरत जताई। यह भी समय की मांग है और इसकी पूर्ति हो, इसे देश के आम लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए। वास्तव में आज जितनी जरूरत राजनीतिक एकजुटता की है उतनी ही सामाजिक एकजुटता की भी। यही एकजुटता हर चुनौती से लड़ने में सहायक बनेगी।

प्रदूषण पर सिर्फ चिंता

वायु प्रदूषण के मामले में दिल्ली के बाद कोलकाता का स्थान आता है। शुक्रवार को बजट पेश करते हुए कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम ने भी स्वीकार किया कि महानगर की हवा लगातार प्रदूषित हो रही है। बावजूद इसके नगर निगम के बजट में वायु प्रदूषण को रोकने व पर्यावरण संरक्षण को लेकर कोई आवंटन नहीं दिखा। प्रदूषण को लेकर सिर्फ कोरी चिंता ही जाहिर हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से लेकर कोलकाता की हवा में प्रदूषण की मात्रा को लेकर समीक्षा करने वाले अन्य संगठनों की रिपोर्ट में बताया गया है कि सड़क, निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल समेत कई और कारण है जिनसे कोलकाता की हवा प्रदूषित हो रही है। इसे लेकर काफी हो-हल्ला भी हुआ था। बावजूद इसके कोलकाता नगर निगम के 2019-20 के बजट में इस समस्या से निपटने के लिए एक शब्द का उल्लेख नहीं है। जलापूर्ति, सड़क, बस्ती, वाणिज्यिक परियोजना, कचरा सफाई समेत कुल छह विभागों में बजट आवंटन की राशि बढ़ाने का उल्लेख किया गया, लेकिन पर्यावरण संरक्षण व प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक भी रुपये खर्च किए जाने का उल्लेख नहीं किया गया। प्रश्न उठता है कि क्या कोलकाता नगर निगम महानगर को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए गंभीर नहीं है। फिरहाद हकीम कुछ माह पहले मेयर बने हैं और उनका यह पहला बजट था, लेकिन शहर को प्रदूषण मुक्त रखने की जिम्मेदारी भी तो उन्हीं की है। हालांकि, नगर निगम के अधिकारियों का तर्क है कि पर्यावरण व प्रदूषण को लेकर अलग से बजट नहीं, लेकिन ग्रीन हाउस व शहरी हरियाली योजना का उल्लेख है। हरियाली से ही प्रदूषण को कम किया जा सकता है, परंतु यहां सवाल यह उठ रहा है कि पौधा लगाने से तत्काल वायु प्रदूषण पर लगाम लग जाएगा? क्योंकि, जब तक पेड़-पौधे बड़े नहीं होंगे तब तक स्थिति नहीं बदलेगी। इसके लिए आवश्यक है कि तत्काल ठोस पहल की जाए। इसके लिए एक समग्र रणनीति बनानी होगी तभी स्थिति में सुधार होगा।

धारा 370 खत्म करने का सही समय

संजय गुप्त

यह धारा 370 का ही दुष्परिणाम है कि तमाम कश्मीरी यह मानने लगे हैं कि वे भारत से अलग हैं। वे कश्मीरियत की बात तो करते है, लेकिन उसे भारतीयता से अलग मानते हैं

आम चुनाव के ठीक पहले कश्मीर में वीभत्स हमले ने पूरे देश को रोष और आक्रोश से भर दिया है। यह हमला जैश ए मोहम्मद के एक कश्मीरी मूल के आतंकी ने अंजाम दिया, जो पहले पत्थरबाज था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए और कई अन्य बुरी तरह घायल भी हुए। इस हमले ने मोदी सरकार पर यह दबाव बढ़ा दिया है कि वह पाकिस्तान को जवाब दे। ऐसी अपेक्षा इसलिए अधिक है कि बीते दो दशकों से पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों ने भारत की नाक में दम कर रखा है। अभी तक भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कदम उठाए हैं वे नाकाफी सिद्ध हुए हैं। उड़ी हमले के बाद सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक का पाकिस्तान पर कोई खास असर नहीं हुआ। इसके पहले पाकिस्तान पोषित आतंकी संगठनों ने जब-जब भारतीय ठिकानों पर हमला किया तब-तब भारतीय नेतृत्व देर-सबेर पाकिस्तान से बातचीत करने पर सहमत हो गया। मुंबई में होटल ताज और अन्य स्थानों पर हुए भीषण आतंकी हमले में करीब एक सौ सत्तर निर्दोष-निहत्थे लोग मारे गए थे। देश तब भी आक्रोश से उबल पड़ा था और हर तरफ से यह आवाज उठी थी कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान ने देश-दुनिया को हिला देने वाले इस हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कुछ नहीं किया और फिर भी कुछ समय बाद भारत पाकिस्तान से बातचीत करने लग गया। ऐसा ही गुरदासपुर, पठानकोट आदि में आतंकी हमले के बाद किया गया। इससे पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा और उसने भारत को परेशान करना जारी रखा। देखना है कि पुलवामा हमले के बाद क्या होता है? पुलवामा की घटना के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया हुआ सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र का दर्जा अवश्य छीन लिया है, लेकिन यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था।

पुलवामा में इतना बड़ा हमला स्थानीय लोगों की मदद के बिना नहीं हो सकता। चिंता की बात यह है कि आने वाले समय में इस तरह के हमले बढ़ने की आशंका है, क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका तालिबान से समझौता करने की कोशिश में है। यह समझौता तालिबान और ऐसे ही अन्य आतंकियों के साथ पाकिस्तान का भी मनोबल बढ़ाएगा। इसके चलते कश्मीर में आतंकियों की आमद और उनकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसका अंदेशा इसलिए है, क्योंकि कश्मीर में जैश, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन सरीखे संगठन अपनी पैठ बनाए हुए हैं। ऐसे संगठनों की सक्रियता के चलते ही कश्मीरी अपनी सूफी संस्कृति को भूलकर चरमपंथ के रास्ते पर जा रहे हैं। इसी कारण पाकिस्तान को कश्मीर में दखल देने में आसानी हो रही है। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जिस जैश ए मोहम्मद ने अपने सिर ली वह वही आतंकी संगठन है जिसने पठानकोट एयरबेस पर हमला किया था। इसके सरगना मसूद अजहर को कंधार विमान अपरहण कांड के वक्त रिहा करना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र ने जैश पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन उसके सरगना मसूद पर पाबंदी के प्रयास इसलिए सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि चीन अड़ंगा लगाए हुए है। वह जिस तरह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मसूद अजहर पर पाबंदी नहीं लगने दे रहा उससे यह साफ है कि वह भारत को नीचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है।

अवधेश राजपूत

देश का राजनीतिक नेतृत्व इससे अपरिचित नहीं हो सकता कि कश्मीरी जनता का एक वर्ग किस तरह कश्मीर गए भारतीयों को विदेशियों की तरह देखता है। इसी कारण घाटी में तैनात सुरक्षा बलों के परिजन सदैव उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। घाटी के लोग भारत विरोधी मानसिकता से तब ग्रस्त हैं जब वहां केंद्र सरकारों ने पानी की तरह पैसा बहाया है। यह पैसा नेताओं की जेबों में अधिक गया है। वहां की औसत जनता को लगता है कि दिल्ली उनकी अनदेखी कर रही है, जबकि इस अनदेखी की जड़ में कश्मीर के दल हैं। वहां अलगाववादी संगठनों के साथ बुद्धिजीवियों और मजहबी नेताओं की एक ऐसी जमात भी तैयार हो गई है जो सदैव कश्मीरी जनता को भड़काने की ताक में रहती है।

इस पर हैरानी नहीं कि पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान से बदला लेने की मांग तेज हुई है। लोग गुस्से में हैं और वे यह चाहते हैं कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए। यह गुस्सा स्वाभाविक है। पाकिस्तान को यह संदेश देना जरूरी है कि वह इसी तरह कश्मीर में खून-खराबा नहीं कर सकता, लेकिन क्या पाकिस्तान के खिलाफ एक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई से कश्मीर में शांति आ जाएगी? दिल्ली में बैठे नीति-नियंताओं को कश्मीर घाटी के प्रति अपना नजरिया बदलना होगा। कश्मीर में जो ऐतिहासिक भूलें हुई हैं उन सबको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ का प्रतिकार अवश्य किया जा सकता है, जैसे धारा 370 को समाप्त करना। यह धारा कश्मीर में अलगाववाद की भावना को बढ़ाने का काम कर रही है। यह सही समय है जब केंद्र सरकार धारा 370 खत्म करने की दिशा में आगे बढ़े। संसद का एक आपातकालीन विशेष सत्र केवल इसलिए बुलाया जाए ताकि इस अलगाववादी धारा को खत्म किया जा सके। कुछ दल इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन देश यह देखेगा कि कौन अलगाववाद को पोषित करने वाले संवैधानिक प्रावधान के साथ है और कौन विरोध में? ध्यान रहे धारा 370 एक अस्थायी धारा है और इसे नेशनल कांफ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला के दबाव में शामिल किया गया था। देश के तत्कालीन नेतृत्व ने शेख अब्दुल्ला के दबाव में आकर जो भूल की उसके ही दुष्परिणाम अब हद से ज्यादा बढ़ गए हैं।

हमारे राजनीतिक नेतृत्व को जहां यह समझने की जरूरत है कि कश्मीर को सही रास्ते पर लाए बगैर पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जा सकता वहीं यह भी कि यह धारा 370 का ही दुष्परिणाम है कि तमाम कश्मीरी यह मानने लगे हैं कि उन्हें विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं और वे भारत से अलग हैं। वे कश्मीरियत की बात तो करते है, लेकिन उसे भारतीयता से अलग मानते हैं। इस मानसिकता का प्रतिकार हर हाल में करना होगा। इसके लिए कश्मीर के अलगाववादी संगठनों के खिलाफ भी सख्ती जरूरी है और वहां के दलों के प्रति भी। नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी सरीखे दलों से ज्यादा उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। ये जब भी विपक्ष में होते हैं, अलगाववादियों के सुर में ही बात करते हैं। यह भी समझने की जरूरत है कि हुर्रियत सरीखे संगठनों को पलने देना भारतीय हितों की अनदेखी करना है।

अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना और सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है तब यह उम्मीद की जाती है कि वे देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में समर्थ होंगे, लेकिन इसी के साथ यह भी उम्मीद की जाती है कि कश्मीर में अलगाववाद और आतंक के विष के जो बीज बोए गए और जो अब वृक्ष बन गए हैं उन्हें जड़-मूल से उखाड़ने का भी काम किया जाएगा। इसमें कश्मीर के राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन समेत अन्य जो भी बाधक बने उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए।

response@jagran.com

कैंसर से लड़ाई की एक बड़ी पहल

उत्तर प्रदेश और बिहार आबादी के लिहाज से देश के दो सबसे बड़े राज्य हैं। कैंसर के सबसे ज्यादा मरीज भी इन दो राज्यों में ही हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आइसीएमआर के आंकड़ों से भी इसकी पुष्टि होती है। इन आंकड़ों के अनुसार देश में कैंसर के कारण सबसे ज्यादा मौतें अकेले उत्तर प्रदेश में होती हैं। राज्य में इस बीमारी की व्यापकता और भयावहता के बावजूद यहां उसके उपचार के लिए सुविधाओं के अभाव ने स्थिति को और बिगाड़ा, क्योंकि यहां कुछ ही अस्पतालों में विशेष सुविधाएं हैं। यहां तक कि बीएचयू स्थित अति विशिष्ट संस्थान माने जाने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी कैंसर के उचित इलाज के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव रहा है। ऐसा अनुमान है कि केवल वाराणसी क्षेत्र में कैंसर निदान की सुविधाओं से करीब 1.83 लाख रोगी उपचार का लाभ उठाएंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया ताकि यहां पर ये सुविधाएं बेहतर हो सकें। यहां बनाए जा रहे इस नए कैंसर केयर सेंटर से लगभग 20 करोड़ लोगों तक उपचार की सुविधा पहुंचेगी। इससे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के अलावा पड़ोसी देश नेपाल के लोग भी लाभान्वित होंगे। यहां लोगों को उपचार मिलने से देश के अन्य कैंसर उपचार केंद्रों पर दबाव भी कम होगा।

बीमारी को अगर पनपने ही न दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे में उसकी रोकथाम और शुरुआती स्तर पर ही पहचान कर इलाज करने के लिए जागरूकता का भी प्रसार किया जाएगा। इसके लिए मध्य भारत में स्पेशियलिटी कैंसर सेंटर और यूनिट्स के विकास एवं मार्गदर्शन के लिए एक केंद्र विकसित होगा। यह सेंटर नेशनल कैंसर ग्रिड के लिए एक नोडल के रूप में कार्य करेगा। इस मिशन के लिए पहले कदम के रूप में टाटा मेमोरियल सेंटर यानी टीएमसी द्वारा जून 2017 में जनसंख्या आधारित रजिस्ट्री शुरू की गई ताकि बीमारी का विस्तार और प्रकृति को समझा जा सके। इसमें वाराणसी की कुल अनुमानित 36.77 लाख आबादी को शामिल किया गया। रजिस्ट्री की अंतरिम रिपोर्ट में कैंसर के 1,002 मामले दर्ज हुए जिनमें से 501 मरीजों की मौत हो गई। पुरुषों में मुंह का कैंसर, जीभ, फेफड़ों, गले और प्रोस्टेट कैंसर मुख्य रूप से होता है। वहीं महिलाओं में मुख्य रूप से स्तन कैंसर, गर्भाशय, गाल ब्लैडर, ओवेरी और फेफड़ों के कैंसर से जुड़े मामले ही मुख्य रूप से दिखते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कैंसर से जुड़े अधिकांश मामले देरी से सामने आए और उनमें अक्सर बीच में ही इलाज छोड़ दिया जाता है।

डॉ. आरए बडवे

वाराणसी में बन रहे नए कैंसर केयर सेंटर से लगभग 20 करोड़ लोगों तक उपचार की सुविधा पहुंचेगी

ऐसे में दो संस्थानों पर काम करने का फैसला किया किया गया। एक इंडियन रेलवेज कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर यानी आइआरसीआइ जिसका विस्तार कर बाद में उसका हस्तांतरण टीएमसी को किया जाना है। 180 बेड वाले आइआरसीआइ का नाम होमी भाभा कैंसर अस्पताल (एचबीसीएच) रखा गया है। इसी तरह टीएमसी द्वारा बीएचयू परिसर में 350 बेड का नया महामना पंडित मदनमोहन मालवीय कैंसर सेंटर यानी एमपीएमएमसीसी भी शुरू किया जा रहा है। एमपीएमएमसीसी के निर्माण और एचबीसीएच के कायाकल्प दोनों कामों से टाटा ट्रस्ट जुड़ा रहेगा। इन दोनों इकाइयों में कुल 530 बेड होंगे जहां अत्याधुनिक उपकरणों के साथ नई तकनीक वाला बेहतर इलाज संभव हो सकेगा। फिलहाल दोनों परियोजनाओं का काम द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है जिसमें एचबीसीएच का छह माह में कायाकल्प हो जाएगा तो एमपीएमएमसीसी में भी दस महीनों में सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इन केंद्रों के विकास में प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत रुचि ने भी अहम भूमिका निभाई जिन्होंने इसमें हरसंभव सहयोग किया।

टाटा ट्रस्ट की एक कारपोरेट प्रबंधन टीम ने इस प्रोजेक्ट को संभाला। टीम के सदस्यों को प्रोजेक्ट के साझीदारों के के साथ कार्यस्थल पर तैनात किया गया ताकि कि वे काम की निगरानी कर सकें और समय-सीमा का ध्यान भी रख सकें। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बचाए गए प्रत्येक वर्ष का अर्थ होगा दस हजार से अधिक मरीजों को अत्याधुनिक उपचार प्रदान करना। टाटा मेमोरियल ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ आसपास के इलाकों में कैंसर पर चौतरफा हमला करने की योजना बनाई है। पहला लक्ष्य, 70 प्रतिशत रोके जा सकने वाले कैंसर को रोकना। दूसरा, पूरी तरह ठीक किए जा सकने वाले कैंसर का इलाज। तीसरा, आम कैंसर का उपचार और साथ ही उनके होने के कारणों को उजागर करना। ऐसा मानव संसाधन तैयार करने का भी लक्ष्य है जिसमें कैंसर से निपटने के लिए सेवा-संस्कृति की भावना विकसित हो और उपलब्ध शोध को और बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

(लेखक टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई के निदेशक हैं)

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य | लगातार कम होती केरोसिन की खपत (हजार टन में)

स्रोत: तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

ऊर्जा

पुण्य

जिस कार्य से अपना और दूसरों का अहित हो, वह पाप है और जिससे सभी का हित हो, वह पुण्य है। जब तक दूसरों का भला नहीं होगा, तब तक स्वयं का भी भला नहीं हो सकता और जिससे दूसरों का हित होता है, उससे अपना अहित कभी नहीं होगा। हमारे अच्छे कर्मों का फल पुण्य है, जिससे हम सुख का अनुभव करते हैं जबकि पाप बुरे कर्मों का परिणाम जो दुख का निमित्त बनता है। अनजाने में हमसे कोई गलती हो सकती है और उसके लिए क्षमा मांगी या दी जा सकती है, लेकिन दूसरों का बुरा करने की मंशा से किया गया कर्म पाप है। कर्म का सिद्धांत यही है कि प्रत्येक सकारात्मक कार्य पुण्य, जबकि नकारात्मक कर्म पाप है। इसके अनुरूप ही प्रत्येक व्यक्ति को फल भुगतना पड़ता है। हमारे कर्म से किसी को लाभ मिलता है तो उसका फल भी हमें किसी न किसी रूप में वापस मिलता है। इसी तरह यदि हमारी वजह से किसी को नुकसान होता है तो उसका फल भी हमें अवश्य मिलता है। एक अमीर व्यक्ति रोज सुबह-शाम मंदिर में घी के दीये जलाता था जबकि एक गरीब व्यक्ति रोज शाम को तेल का एक दीपक जलाकर अंधेरे रास्ते में रख आता था। कर्म दोनों व्यक्तियों ने किए, लेकिन दोनों के कर्मों में जमीन-आसमान का अंतर है। मंदिर में पहले से ही दीये जल रहे थे, इसलिए अमीर व्यक्ति के कर्म से किसी का भी भला नहीं हुआ, लेकिन गरीब आदमी के अंधेरी राह में दीपक रखने से कइयों को उसका लाभ मिला और राहगीरों ने जरूर उस गरीब व्यक्ति के लिए दुआएं की होंगी। यानी गरीब आदमी का कर्म एक लक्ष्य से जुड़ा था।

मनुष्य के कर्म की महत्ता उसकी उपयोगिता में ही है। निष्ठा, लगन और एक लक्ष्य के लिए किए गए कर्म में उत्कृष्टता आती है और मनोयोग से किया गया कर्म ही परमात्मा की पूजा है। जिंदगी में सबसे बड़ा पाप दूसरों को पीड़ा पहुंचाना है और सबसे बड़ा पुण्य परोपकार है। हमारे सभी पुराणों का सार भी यही है कि परोपकार करने से पुण्य और परपीड़ा से पाप मिलता है। पुण्य का फल सुख है और पाप का दुख। जिस भी किसी व्यक्ति के दिमाग में दूसरे के लिए बुरे भाव उत्पन्न हों तो उसे स्वयं को उसके स्थान पर रखकर सोचना चाहिए कि यदि कोई उसके बारे में ऐसे बुरे विचार रखता, तो उसे कैसा लगता?

शंभूनाथ पांडेय

धरती के हिलने का लंबा सिलसिला

मुकुल व्यास

कई दिनों तक चलने वाले भूकंप महसूस भी नहीं होते। इनकी पड़ताल से भूकंप की प्रकृति समझने में मदद मिल सकती है

उत्तर-पश्चिमी तुर्की में 2016 की गर्मियों में एक भूकंप आया था जो 50 दिनों तक चला। रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 5.8 आंकी गई थी। इस भूकंप की खास बात यह थी कि इतने दिनों तक चलने के बावजूद किसी ने भी इसे महसूस नहीं किया। इस क्षेत्र में भूकंप का आना कोई असामान्य बात नहीं है, क्योंकि यह पूरा क्षेत्र बहुत ही सक्रिय दरार (फाल्ट लाइन) पर स्थित है जहां अतीत में शक्तिशाली भूकंप आ चुके हैं। विनाशकारी भूकंप तब उत्पन्न होते हैं जब जमीन के नीचे फाल्ट लाइन पर विपरीत दिशाओं में खिसकने वाली दो टेक्टोनिक प्लेटें मिल जाती हैं और अचानक फिसल जाती हैं। इस प्रक्रिया में सारी ऊर्जा एकदम बाहर आती है।

पृथ्वी के बाहरी कवच को लिथोस्फीयर कहते हैं जिसमें पपड़ी और ठोस चट्टानें शामिल होती हैं। इसके नीचे एस्थेनोस्फीयर (पृथ्वी के मैंटल की ऊपरी परत) होता है जो एक तरल पदार्थ की तरह प्रवाहित होता है। पृथ्वी का लिथोस्फीयर टेक्टोनिक प्लेटों में बंटा हुआ है। ये प्लेटें अनियमित आकार की विशाल ठोस चट्टानें हैं। अनुमान है कि एक प्लेट 113 किमी चौड़ी होती है। महाद्वीपों और सागरों के नीचे सात बड़ी प्लेटें और कई छोटी प्लेटें हैं। ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तैरती रहती हैं। तुर्की में 2016 में आया भूकंप दरअसल एक 'धीमा भूकंप' था।

उससे निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा सामान्य भूकंप के बराबर हो सकती है, लेकिन लंबी अवधि तक चलने के कारण इनका प्रभाव महसूस नहीं होता। धीमे भूकंप में टेक्टोनिक प्लेटें फाल्ट लाइन पर धीरे-धीरे आगे सरकती हैं। ऐसे भूकंपों में सामान्य भूकंपों जैसी तरंगें उत्पन्न नहीं होतीं। यानी ये कंपन नहीं पैदा करते, लेकिन इससे मिट्टी की ऊपरी परत में गड़बड़ी पैदा होती है जिसका अध्ययन किया जा सकता है। वर्ष 2016 में तुर्की के मरमारा समुद्र के नीचे फाल्ट लाइन के फिसलने से धीमा भूकंप आया। जीएफजेड जर्मन रिसर्च सेंटर की शोधकर्ता पैट्रिशिया मार्टिनेज-गर्जोन और उनकी टीम ने मरमारा समुद्र में किए गए बोरहोल का इस्तेमाल किया। इन बोरहोल में स्ट्रेन मीटर लगे हुए थे जिन्होंने सतह पर हुई गड़बड़ी को दर्ज किया।

स्ट्रेन मीटरों ने अपने आसपास की चट्टानों की धीमी विकृति को नापा। फ्रांसीसी भूकंप भौतिकविद लूसिल ब्रूहैट ने कहा कि धीमे भूकंप की घटनाएं बहुत सामान्य हैं। दुनिया में सबसे लंबा धीमा भूकंप अलास्का में रिकॉर्ड किया गया था जो नौ वर्ष तक चला। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 दर्ज की गई थी। इस तरह की भूकंपीय घटनाओं से भविष्य में होने वाले नुकसानदायक भूकंपों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। धीमा भूकंप उसी क्षेत्र में एक बड़े भूकंप की शुरुआत कर सकता है। 2011 में जापान में सबसे बड़ा भूकंप आया था जिसके बाद सुनामी भी आई थी। इस बड़े भूकंप से पहले इसी क्षेत्र में एक धीमे भूकंप की शुरुआत हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि संभवतः इसी भूकंपीय घटना से बड़े भूकंप की शुरुआत हुई होगी। फिलहाल वैज्ञानिकों के पास धीमे भूकंपों के बारे में बहुत कम जानकारी है। वैज्ञानिक अभी यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकते कि धीमे भूकंपों के आधार पर बड़े भूकंपों की भविष्यवाणी की जा सकती है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सीएम भी और संपादक भी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की सदस्यता लेना चाहती हैं। दरअसल उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का एक अखबार है 'जागो बंगाल'। उसकी संपादक के तौर पर ममता कोलकाता के प्रेस क्लब की सदस्य हैं। हाल में जब भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुटता दिखाने वह दिल्ली पहुंचीं तो एक शाम प्रेस क्लब भी आ गईं और वहीं खुलासा किया कि वह दिल्ली स्थित प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की सदस्यता भी ले सकती हैं। वह अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं और इसका उदाहरण उस वक्त भी देखने को मिला जब उन्हें पता चला कि साबूदाने का बड़ा बना है। उन्होंने तत्काल अपने लिए दो बड़े पैक करवा लिए और घर की ओर जाते हुए कार में ही उसका जायका लिया।

बैंकों के आगे बाबू भी हुए बेबस

सरकार के तंत्र में नौकरशाही उसका एक ताकतवर हिस्सा है। सरकार को चलाने की पूरी जिम्मेदारी नौकरशाही की है। कोई काम कैसे होना है इसका रास्ता भी राजनेताओं के लिए नौकरशाह ही खोजते रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में अर्थव्यवस्था का एक अंग ऐसा भी है जिसके आगे नौकरशाही भी नतमस्तक है। वह हैं सरकारी बैंक। उद्योग जगत बैंकों से मिलने वाले कर्ज में हुई कमी से परेशान है। ऐसे में एक उद्योगपति ने सरकार के महत्वपूर्ण आर्थिक मंत्रालय के सचिव से दोस्ताना लहजे में पूछ ही लिया कि आखिर क्या वजह है कि सरकार बैंकों को कर्ज की रफ्तार बढ़ाने को नहीं कह रही? बताते हैं सचिव ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि क्या किया जाए, सरकारी बैंक हैं कि सुनने को राजी नहीं। लिहाजा अब सरकारी बैंकों को अधिकारियों ने कहना ही बंद कर दिया है।

राजरंग

अधूरी तैयारी ने कराई जगहंसाई

महकमे में मातहतों पर गुस्सा होना या झल्ला पड़ना वैसे तो आम बात है, लेकिन मामला यदि राज्यसभा जैसे उच्च सदन का हो तो थोड़ा हैरान जरूर करता है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बजट सत्र के अंतिम दिन राज्यसभा में अंतरिम बजट पारित होना था। विभाग के जूनियर मंत्री को इस काम के लिए लगाया गया था। इस बीच जैसे ही उनकी बारी आई और वह बोलने के लिए खड़े हुए तो पता चला कि वह कागज ही उनके पास नहीं है। आखिर में उन्होंने फाइलों को हड़बड़ी में तेजी से पलटते हुए अफसरों पर तेज-तेज चिल्लाना शुरू कर दिया। यह सब जब हो रहा था, उस समय माइक और कैमरा दोनों ही ऑन थे। ऐसे में वह जो भी बोल रहे थे, उनकी पूरी बात सदन में गूंज रही थी। देखते ही देखते सदन में ठहाके गूंजने लगे। आखिर में पास बैठे साथी मंत्री ने जब उन्हें रोका, तब वह भी समझ पाए और चुप हुए। हालांकि मौके की नजाकत को समझ सभापति ने सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ा दिया। इसके बाद ही मंत्री ने राहत की सांस ली।

सब कुछ बदल गया

आम चुनाव से चार-पांच महीने पहले का समय विदेश मंत्रालय के लिए काफी आराम और सुकून वाला माना जाता है। इसकी भी अपनी तमाम वजहें होती हैं। इस दौरान न कोई खास उच्चस्तरीय दौरा होता है और न ही कोई बाहरी मेहमान ही दौरे पर आते हैं, क्योंकि सरकार की वरीयता में कूटनीति थोड़ी नीचे होती है। अधिकारियों को छुट्टियां भी आसानी से मिलती हैं और बड़े अधिकारी नई सरकार का इंतजार करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा था, लेकिन पुलवामा हमले ने सब कुछ बदल दिया। विदेश मंत्रालय में जो सक्रियता दिखी वैसी कभी कभार ही देखने को मिलती है। हमले के दिन ही विदेश मंत्रालय में देर रात तक अधिकारियों के बीच विमर्श होता रहा और कई बैठकों का दौर चला। पाकिस्तान से लेकर जापान तक के 25 देशों के राजनयिकों से कुछ ही घंटे में मुलाकात का न केवल एजेंडा तैयार हुआ, बल्कि उस पर अमल भी हुआ। इस तरह देखा जाए तो राजग के कार्यकाल में विदेश मंत्रालय की व्यस्तता शुरू से लेकर आखिर तक बनी हुई है।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।